बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 155

बदलाव के मोड़ पर

भारत बहुत जल्दी बदलाव के एक खास मोड़ पर पहुंचने वाला है। तेल एवं रत्न-आभूषण क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो देश का सेवा निर्यात जल्दी ही वस्तु निर्यात से ज्यादा हो जाएगा। इस वित्त वर्ष के पहले चार महीने में सेवा निर्यात से 74.05 अरब डॉलर की राशि आई जो वस्त्र निर्यात (तेल एवं रत्नाभूषण को छोड़कर) से हासिल 79.81 अरब डॉलर की राशि से कुछ ही कम है। चूंकि सेवा निर्यात 8 फीसदी की दर से बढ़ रहा है और वस्तु निर्यात की वृद्धि दर 2 फीसदी से भी कम है, ऐसे में बदलाव एक या दो वर्ष से ज्यादा दूर नहीं है।

यह घटनाक्रम असाधारण होगा और जरूरी नहीं कि यह अच्छा ही हो। वैश्विक स्तर पर कुल कारोबार में सेवा व्यापार की हिस्सेदारी 20 फीसदी से भी कम है। भारत की बात करें तो तेल एवं वस्त्र-आभूषण समेत कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 40 फीसदी है। इसे इससे अधिक भी कहा जा सकता है क्योंकि वस्त्र एवं आभूषणों को वस्तु निर्यात में शामिल किया जाता है जबकि हकीकत में जो निर्यात किया जा रहा है वह उन लोगों के काम की बदौलत होता है जो आयातित हीरे को काटने और चमकाने का काम करते हैं। आधिकारिक वर्गीकरण चाहे जो भी हो, यह सेवा का निर्यात है।

इस सेवा-निर्माण दलील में जबरदस्त विडंबना है। सन 1980 में अमेरिका ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा कि वैश्विक व्यापार वार्ताओं के नये दौर के दायरे का विस्तार करके न केवल वाणिज्यिक वस्तुओं बल्कि सेवा व्यापार को भी उसमें शामिल किया जाए। उस वक्त भारत ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि बाजारों को सेवा क्षेत्र के व्यापार के लिए नहीं खोला जाना चाहिए। मेरे साथी स्तंभकार टीसीए श्रीनिवास-राघवन उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कहा था कि भारत को इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी लाभ मिल सकता है (हमारे पास अन्य तमाम देशों की तुलना में सस्ती तकनीक, चिकित्सक, अंकेक्षक, अंतरिक्ष विज्ञानी आदि हैं)। परंतु उनकी आवाज अमेरिका विरोधी शोरगुल में खो गई।

आज परिस्थितियां एकदम उलटी हो चुकी हैं। क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी सहयोग (आरसीईपी) को लेकर लंबी बातचीत में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष दो क्षेत्रों में यह पेशकश कर रहा है कि अगर वे सेवा व्यापार खोलते हैं तो वह वस्तु व्यापार में और खुलापन लाएगा। किसी का प्रत्युत्तर नहीं आया और आरसीईपी अटका हुआ है।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

अन्य विडंबनाओं पर नजर डालते हैं। भारत जिन अन्य चीजों के लिए जोर दे रहा है उनमें कुछ ऐसी चीजों का उदारीकरण शामिल है जो बहुपक्षीय व्यापार सेवा समझौतों के 'मोड 4' में वर्गीकृत हैं। इसमें 'प्राकृतिक मनुष्यों' का आवागमन भी शामिल है। इसके पीछे दलील यह है कि अन्य देशों को भारत के कामगार प्रवासियों को इजाजत देनी चाहिए (एच1बी वीजा के बारे में विचार कीजिए)। इसके उलट दलील यह है कि भारत बांग्लादेश से प्रवासियों के आगमन को रोकने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि प्राकृतिक लोगों का आवागमन व्यापार का नहीं नागरिकता का मुद्दा है। सामान्य समझ कहती है कि दोनों बातें सही हैं।

विभिन्न देश अपने हित को ध्यान में रखकर काम कर सकते हैं और वे ऐसा करते भी हैं। ऐसे में आर्थिक मामलों के प्रभारियों की चिंता वार्ता की रणनीतिक स्थिति नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमियां होनी चाहिए। ये वे कमियां हैं जो निर्यात के रुझान में साफ नजर आती हैं। घरेलू विनिर्माण की विफलता, खासकर मेक इन इंडिया की नाकामी और जीडीपी में सेवा व्यापार की असंगत होती हिस्सेदारी। यह बात ध्यान रहे कि उच्च मूल्यवर्धन वाला सेवा निर्यात विनिर्माण से कम रोजगार उत्पन्न करता है।

इसके बावजूद संभावना यही है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का असंतुलन आगे बढ़ेगा। दरअसल सेवा निर्यात के कुछ ऐसे क्षेत्र का लाभ उठाना आसान है जो अब तक दायरे से बाहर रहे जबकि विनिर्माण को बेहतर बनाने के लिए देश के बुनियादी ढांचे में सुधार करना कहीं अधिक मुश्किल है। बिजली, भूमि, परिवहन, बंदरगाह शुल्क, नौवहन दरों की ऊंची लागत और श्रम बाजार की अक्षमताओं आदि के साथ-साथ रुपये की विनिमय दर ने वस्तु निर्यात को प्रभावित किया है। यह सही है कि सेवा निर्यात सफल हो रहा है लेकिन रुपया मजबूत होने के साथ-साथ कम मार्जिन पर काम करने वाला विनिर्माण क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक गैर प्रतिस्पर्धी होता जाएगा। इसका असर ग्रामीण क्षेत्र के लाखों युवाओं के लिए घरेलू स्तर पर रोजगार की कमी के रूप में सामने आएगा।

विनय सिन्हा

हकीकत में बदलता सीडीएस का पद

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की अवधारणा में सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशनल थिएटर कमांड को इस पद के अधीन रखा जाए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **प्रेमवीर दास**

रक्षा क्षेत्र की कमजोरियों पर इसी समाचार पत्र में लिखे एक लेख में मैंने करीब एक महीने पहले कहा था कि दो दशक की चर्चा और बहस के बावजूद पिछली सरकारें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) की जरूरत पर कोई निर्णय नहीं ले सकीं। मैंने यह भी कहा था कि केवल मौजूदा प्रधानमंत्री के पास यह क्षमता है कि वह नोटबंदी की तरह विपक्ष की आलोचना की परवाह किए बिना यह कदम उठा सकें। मेरी यह धारणा सही साबित होती दिख रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से यह घोषणा कर दी कि देश में सीडीएस की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सशस्त्र बलों को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और एकजुट करने में मदद मिलेगी।

अब यह बात लगभग सभी जानते हैं कि वाजपेयी सरकार ने करगिल युद्ध के बाद स्वर्गीय के सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति (केआरसी) का गठन किया था। इस समिति को समूची सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया था। केआरसी ने कई अनुशंसाएं की थीं, उनमें एक महत्त्वपूर्ण अनुशंसा सीडीएस का पद सृजित करने की भी थी। इसके पश्चात तत्कालीन उप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह नियुक्त किया गया। इस समूह ने चार कार्य समूहों का गठन किया जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। इनमें से एक था उच्च रक्षा प्रबंधन जिसकी अध्यक्षता पूर्व रक्षा राज्य मंत्री अरुण सिंह कर रहे थे। मैं इस समूह का एक मात्र सेवानिवृत्त समूह था। शेष अन्य सदस्य सेवारत सैन्य अथवा असैन्य अधिकारी थे।

अरुण सिंह समिति में तमाम वरिष्ठ सैन्य-असैन्य अधिकारियों को शामिल किया गया था। इनमें छह रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के करीब 17 पूर्व प्रमुखों के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान विकास एवं उत्पादन क्षेत्र के उच्च पदस्थ लोग भी शामिल थे।

यह समिति सैन्य मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ तीन अन्य कार्यबलों के साथ निरंतर संवाद में रहती थी। शेष तीन कार्यबल क्रमश: खुफिया सेवा, सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को लेकर काम कर रहे थे। इन तीनों समूहों में केवल सेवानिवृत्त अधिकारी ही शामिल किए गए थे जो सरकार की निर्णय प्रक्रिया में उच्च पदों पर आसीन रहते थे। महज चार महीनों में इन समूहों ने एक बैठक में मंत्री समूह के समक्ष अपने प्रस्ताव पेश कर दिए। उस बैठक में मैं मौजूद था और मुझे याद आता है कि अरुण सिंह के कार्यबल ने उच्च रक्षा प्रबंधन को लेकर जो भी अनुशंसाएं की थीं, मंत्री समूह ने उन्हें स्वीकार कर लिया और वे मूल अनुशंसा में शामिल हो गईं। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन।

यहां यह बताना उचित होगा कि चर्चा में शामिल तमाम वायुसेना प्रमुखों ने सीडीएस के विचार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि इसका सेनाओं की लड़ाकू क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय की अफसरशाही में इसलिए नकारात्मकता थी क्योंकि माना जा रहा था कि यह निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका को नुकसान पहुंचाएगा। इन प्रतिकूल विचारों के बीच अरुण सिंह को अपनी अनुशंसाएं देनी पड़ीं। हमारे समूह ने यह प्रस्ताव रखा कि सीडीएस द्वारा नियोजन, सिद्धांत और सेना विकास कार्यक्रम के संचालन के साथ-साथ खुफिया विभाग कभी निगरानी करनी चाहिए और सेना प्रमुखों के पास संचालन की शक्ति रहनी चाहिए।

यह महसूस किया गया कि समय बीतने के साथ-साथ उनके नियंत्रण का दायरा नए सिरे से समायोजित हो जाएगा। यह एक बड़ा समझौता था जो तत्कालीन प्रधानमंत्री की मंजूरी नहीं हासिल कर सका। नौसेना के तत्कालीन चीफ एडमिरल सुशील कुमार की हाल में आई पुस्तक के मुताबिक तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, 'इसके बारे में और सोचना पड़ेगा।' मामला पिछले 18 वर्षों से वहीं अटका हुआ है। मोदी ने इस मसले पर जबरदस्त साहस दिखाया है, जिसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए।

परंतु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमाम बड़ी सशस्त्र सेनाओं में सीडीएस है। उन्होंने अमेरिका का उल्लेख खासतौर पर किया। यह सही है कि अमेरिका में तथा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन आदि देशों में सीडीएस योजना निर्माण और सैन्य विकास की निगरानी नहीं करता। यह काम व्यक्तिगत सेना प्रमुखों के पास रहता है लेकिन संचालन का नियंत्रण सीडीएस के हाथ में रहता है।

यह बात समझी जा सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस संयुक्त और एकीकृत व्यवस्था पर जोर दिया है, वे दोनों बातें यहां लागू होती हैं। केवल पाकिस्तान में ही सीडीएस इन अहम लेकिन नीरस कामों को अंजाम देता है परंतु अंतिम निर्णय सेना प्रमुखों, उनमें भी थल सेना प्रमुख का होता है। आशा की जानी चाहिए कि हमारे होने वाले सीडीएस को इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे में सीडीएस के गठन का निर्णय जहां साहसिक था क्योंकि इसे काफी विरोध के बीच अंजाम दिया गया ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पद केवल सजावटी नहीं होगा बल्कि इसके पास तमाम जरूरी अधिकार होंगे। केवल परिचालन के नियंत्रण से ही ये दोनों हासिल हो सकते हैं। एक बात और निश्चित है कि विभिन्न सेवाओं के प्रमुखों की ओर से इसका विरोध होगा। वे इसे अपने अधिकारों का अतिक्रमण मानेंगे परंतु जैसा कि मैंने कहा प्रधानमंत्री इस बात से निपट सकते हैं।

सीडीएस की अवधारणा से जुड़ी एक बात यह भी है कि ऑपरेशनल थिएटर कमांड को उनके अधीन लाना होगा। सेना, नौसेना और वायुसेना के दरमियान ऐसी 12 कमांड हैं। अंडमान एवं निकोबार कमांड को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए और जानकारी के मुताबिक दो अन्य कमांड अभी प्रक्रियाधीन हैं। चूंकि हमने उच्च रक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में अमेरिका का उदाहरण लिया है इसलिए हमें भी उस राह पर चलना चाहिए। हमारे यहां कामकाज का मौजूदा तरीका बहुत पुराना है और उसमें सुधार काफी लंबे समय से लंबित है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपनी बातों पर अमल करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे।

(लेखक उच्चतर रक्षा प्रबंधन संबंधी कार्यबल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं)

लगातार जारी है ज़ी समूह की नीतिगत साझेदार की तलाश

उम्मीद की जा रही थी कि कोई नीतिगत विदेशी निवेशक शुरुआती पेशकश करेगा लेकिन अंतत: यह वित्तीय लेनदेन के रूप में सामने आया। यह कहना है मीडिया पार्टनर्स एशिया के उपाध्यक्ष (भारत) मिहिर शर्मा का। इस बात में देश के सबसे प्रतीक्षित मीडिया सौदे का लब्बोलुआब छिपा हुआ है। तकरीबन नौ महीने की अटकलबाज़ी के बाद कॉमकास्ट, सोनी या रिलायंस जियो के बजाय अमेरिका की इन्वेस्को ओपनहाइमर डेवलपिंग मार्केट्स फंड ने ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में 11 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी। कंपनी ने 31 जुलाई को हुए सौदे में इसके लिए 4,224 करोड़ रुपये की राशि चुकाई।

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

ज़ी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में शामिल है। इसके 10 भाषाओं में 41 चैनल हैं जिनकी टेलीविजन दर्शकों में 19 फीसदी हिस्सेदारी है। जबकि उसके ओटीटी ब्रांड ज़ी 5 को भी काफी लोकप्रियता मिल रही है। यह इकलौता समूह है जो डिज्नी के स्टार इंडिया को कड़ी टक्कर दे रहा है जो इस समय नेटवर्क हिस्सेदारी में दूसरे स्थान पर है।

ज़ी देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनियों में शामिल है। इसके 10 भाषाओं में 41 चैनल हैं जिनकी टेलीविजन दर्शकों में 19 फीसदी हिस्सेदारी है। जबकि उसके ओटीटी ब्रांड ज़ी 5 को भी काफी लोकप्रियता मिल रही है। यह इकलौता समूह है जो डिज्नी के स्टार इंडिया को कड़ी टक्कर दे रहा है जो इस समय नेटवर्क हिस्सेदारी में दूसरे स्थान पर है। 7,934 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष में इसकी ब्याज, कर, अवमूल्यन के पूर्व आय 2,564 करोड़ रुपये रही। गत पांच वर्ष में इसमें 16.3 फीसदी की दर से बढ़ोतरी हुई है।

जब 4.3 अरब डॉलर मूल्य के एस्सेल समूह के चेयरमैन और ज़ी को खड़ा करने वाले सुभाष चंद्रा ने कहा कि उनकी कंपनी वैश्विक प्रसार के लिए नीतिगत साझेदार तलाश कर रही है तो इस खबर पर काफी उत्साह देखने को मिला।

विनिवेश की पहली प्रेरणा बना डिज्नी और फॉक्स के बीच हुआ सौदा। इस सौदे ने भारत में 1,67,400 करोड़ रुपये के मीडिया और मनोरंजन बाजार में हलचल मचा दी। यह अधिक बड़ा और तकनीक केंद्रित हो गया। 137 अरब डॉलर की अल्फाबेट (गूगल और यूट्यूब की मूल कंपनी) और 94.5 अरब डॉलर की कॉमकास्ट के बाद 60 अरब डॉलर मूल्य की डिज्नी भी दुनिया की बड़ी मीडिया कंपनियों में शुमार है।

स्टार इंडिया में 13,825 करोड़ रुपये का उसका स्वामित्व बताता है कि उसकी लड़ाई 38,838 करोड़ रुपये अथवा 5.5 अरब डॉलर मूल्य की रिलायंस जियो (जिसके पास कई अन्य कंपनियों के साथ वॉयकाम 18 का मालिकाना है) और सोनी से है जिसका कारोबार एक अरब डॉलर से कुछ ही कम है। कॉमकास्ट और ज़ी अगर मिल जाते तो उनके लिए डिज्नी-स्टार या रिलायंस जियो का मुकाबला करना आसान था।

बहरहाल, दूसरी बात। समूह स्तर पर एस्सेल पर 17,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम कर्ज होने की बात कही जा रही है और इसकी प्रतिभूति प्रवर्तक के विभिन्न कारोबार में उसकी हिस्सेदारी है। कंपनी को ऋणमुक्त करने का एक मात्र तरीका विभिन्न मीडिया और गैर मीडिया कारोबार में हिस्सेदारी बेचना है। इन्वेस्को के पास पिछले 17 वर्ष से ज़ी की 8 फीसदी हिस्सेदारी है और अब उसने 11 फीसदी हिस्सेदारी और खरीद ली है।

परंतु इस सौदे से कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि वह कर्जदारों को जाएगा। न ही इस सौदे से कंपनी को कोई नीतिगत साझेदार मिला। ज़ी के सीईओ और प्रबंध निदेशक पुनीत गोयनका ने कहा कि यह एक अच्छा सौदा है क्योंकि यह समय पर पूरा हो सका। समूह को इस वर्ष 30 सितंबर के पहले अपने कर्जदारों के साथ मामला निपटाना था। गोयनका कहते हैं कि अगर अधिक समय होता तो शायद समूह नीतिगत साझेदार तलाश करती। परंतु चूंकि कंपनी 25 जनवरी को शेयरों में 30 फीसदी गिरावट के बाद से लगातार संघर्ष कर रही थी इसलिए उनको लगता है कि नीतिगत साझेदार मोलभाव कर रहे थे।

इसमें चकित करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि यह एक अच्छी संपत्ति की परेशानी में की गई बिक्री है। गोयनका इस बात से प्रसन्न हैं कि ज़ी के शेयरों का आधार मूल्य नए सिरे से तय हुआ है। इन्वेस्को ने कंपनी के शेयर 400 रुपये प्रति शेयर के मूल्य पर खरीदे। यह उस वक्त के 360 रुपये प्रति शेयर के बाजार मूल्य से अधिक था। जुलाई के अंतर से यह और गिरकर 330 रुपये प्रति शेयर के करीब आ गया था। कंपनी के प्रवर्तकों के पास अभी भी ज़ी के करीब 25 फीसदी शेयर बचे हुए हैं और उन्होंने नीतिगत निवेशक को एक और बिक्री से इनकार नहीं किया है। इससे प्रबंधन पर परिवार का नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है लेकिन अगर रुपर्ट मर्डोक फॉक्स को एक बड़ी प्रतिद्वंद्वी को बेच सकते हैं तो सुभाष चंद्रा क्यों नहीं?

कानाफूसी

नाराजगी पर मतभेद

केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने को लेकर संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए को लेकर जो निर्णय लिया उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। परंतु इस विषय को लेकर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के भीतर नेताओं की राय बंटी हुई है। जदयू बिहार में भाजपा की सहयोगी है। पार्टी का एक धड़ा जहां केंद्र का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा धड़ा इसके खिलाफ है। पार्टी नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी इसके खिलाफ थी लेकिन कानून बनने के बाद विरोध का कोई तुक नहीं है। कुछ मंत्री अभी भी विरोध कर रहे हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं ने वादा किया था कि कश्मीर में यथास्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर वे अपना वादा तोड़ रहे हैं तो विरोध तो होगा।

सबूत लाओ

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के कुछ ही महीनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भी 2024 के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी ने महत्त्वाकांक्षी सदस्यता अभियान शुरू किया है। पार्टी के सांसदों और विधायकों से कहा गया है कि वे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बताएं कि वे इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं और नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए आयोजित कार्यक्रमों की सूची तथा इस अवसर पर खींची गई तस्वीरों को बतौर सबूत पार्टी के पास जमा कराएं। पार्टी का कहना है कि उसने प्रदेश में 40 लाख नए सदस्य बनाए हैं और वह जल्दी ही 10 लाख नए सदस्य और बनाने जा रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इस सदस्यता अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका दावा है कि अभियान के दौरान भाजपा ने देश भर में तीन करोड़ नए सदस्य बनाए हैं।

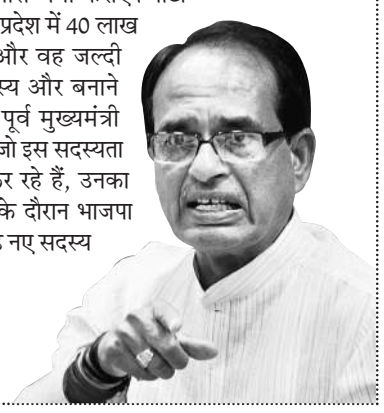

आपका पक्ष

लोगों में बचत की भावना उत्पन्न करना

वर्तमान समय में लोगों में बचत की भावना उत्पन्न करना जरूरी हो गया है। बचत का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं है बल्कि सभी चीजों से है। पूरे विश्व के साथ ही देश में जल संकट गहराने लगा है। इसका समाधान पानी की बचत करना ही है। खाद्यान्न संकट से निजात पाने के लिए भी अन्न की बचत जरूरी हो गई है। भारत को आर्थिक मंदी का सामना नहीं करना पड़े तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए भी बेवजह खर्च से बचने की जरूरत है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में आज अधिकतर लेनदेन कार्ड से हो रहा है। इससे नोटों का चलन काफी कम हो गया है जिससे अधिक नोट छापने की जरूरत नहीं रह गई है। इसका फायदा रिजर्व बैंक को नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले कागज तथा रंग में बचत होगी। आधुनिक युग में लोग बचत करना भूल गए हैं। पहले जमाने में लोग काफी बचत करते थे। चाहे वह अन्न हो या पैसे या कुछ और चीजें। लोग उतना ही भोजन लेते थे जितना वह खा सके। इससे अन्न बेकार नहीं जाता था। आज होटलों तथा रेस्टोरेंट में काफी अन्न बरबाद चला जाता है। इससे अन्न तो बरबाद होता ही है ग्राहक को पैसे भी अधिक लगते हैं। अगर बचत की भावना होगी और पूरा देश बचत में सहयोग करेगा तो देश काफी कुछ बचा सकता है। इसी प्रकार घर पर भी भोजन की बरबादी रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे देश की अर्थव्यवस्था के साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

दीप्ति कुमारी, नई दिल्ली

जल संकट से निजात पाने के लिए लोगों को पानी की बचत के लिए प्रेरित करना होगा

सेना को मजबूत करने का समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का पद सृजित किया जाएगा। इससे तीनों सेना के बीच सामंजस्य बनेगा जिससे किसी भी आपात स्थिति में सरकार को सेना के तीनों अंगों से जानकारी फौरन मिलेगी तथा सेनाओं को निर्देश भी मिल सकेगा। कश्मीर मामले के बाद यह और भी जरूरी हो गया है क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीमा पर अपनी सेना बढ़ा रहा है। देश की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति ने जैसे अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को हटाया है इसे देख यह कल्पना की जा सकती है कि अब कब्जे वाले कश्मीर तथा अकसाई चिन भी भारत वापस पा सकेगा। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की कार्रवाई का विरोध कर रहा है लेकिन उसे ही मुंह की खानी पड़ रही है और भारत को विश्व के कई देशों का समर्थन मिल रहा है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।